कोयतुरो की बुलन्द आवाज

# कोयतुर टाइम्स

KOYTUR TIMES
www.koyturtimes.com

**सुविचार -**

**"हार मत मानो, जीत तुम्हारे ही कदमों में है।"**

सोमवार 20 जनवरी 2025 | RNI: UDYAM-CG-11-0005844 | www.koyturtimes.com

# शानदार 'दिव्य कला शक्ति' प्रदर्शन के साथ वडोदरा में दिव्य कला मेला संपन्न हुआ

नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले की गरिमामयी उपस्थिति में दिव्य कला मेले का भव्य समापन समारोह अकोटा स्टेडियम, वडोदरा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुति से हुई। श्री अठावले ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में दिव्यांगजनों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "2047 में, जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, हमारे दिव्यांगजन पूरी दुनिया को प्रेरित करेंगे।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दिव्यांगजनों के लिए उद्यमिता, कौशल विकास और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को लागू किया गया है। इस अवसर पर एनडीएफडीसी के सीएमडी श्री नवीन शाह ने कहा कि यह 23वां मेला है, जो दिव्यांगजन उत्पादों के आर्थिक सशक्तिकरण और विपणन के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। 9 से 19 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस 11 दिवसीय मेले ने दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों ने भाग लिया। गुजरात के 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इरकॉन के सीएसआर फंड के ज़रिए 11 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित की गईं, और एलिम्को द्वारा 14 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। 17 जनवरी को दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार मेले का भी आयोजन किया गया, जहां समापन समारोह के दौरान 18 दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये। 'दिव्य कला शक्ति' सांस्कृतिक कार्यक्रम में 15 राज्यों के 78 प्रतिभाशाली दिव्यांग कलाकार शामिल हुए, जिन्होंने 36 मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत 'जय जय गर्वी गुजरात' गीत पर समूह नृत्य से हुई। जम्मू-कश्मीर की स्वाति ने लगान फिल्म के गीत, 'राधा कैसे ना जले' पर मनमोहक डांस किया। ओडिशा की संयोतनी समदर ने अपने शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह में ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद के कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शन देखा गया। अर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, समर्थ ग्रुप और पार्थ ग्रुप जैसे संस्थानों के कलाकारों ने भी कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ दीं। जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कलाकारों ने हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई और पैकेज्ड भोजन सहित अपने अनोखे उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिससे 'वोकल फॉर लोकल' पहल को भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रदर्शन और विविध किस्म के खाने की स्टालों ने कार्यक्रम के आकर्षण को और बढ़ा दिया।

## प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस पर इसके बहादुर कर्मियों को सलाम किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के बहादुर कर्मियों के साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए आज बल के स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा ''राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के स्थापना दिवस के इस विशेष अवसर पर, हम उन बहादुर कर्मियों के साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा को सलाम करते हैं, जो विपत्ति के समय में एक ढाल की तरह काम करते हैं। जीवन बचाने, आपदाओं से निपटने और आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। एनडीआरएफ ने आपदा मोचन और प्रबंधन में वैश्विक मानक भी स्थापित किए हैं।

## महाकुंभ 2025: लाखों श्रद्धालुओं के लिए FSSAI की सख्त निगरानी में सुरक्षित भोजन की व्यवस्था

संवाददाता | प्रयागराज

प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विशेष इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहयोग से, मेले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को तैनात किया गया है। ये प्रयोगशालाएं मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कर रही हैं और मिलावट की संभावना को खत्म करने के लिए सतर्कता बरत रही हैं। मेले के लिए पूरे क्षेत्र को 5 जोन और 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) तैनात किए गए हैं, जबकि जोनों की निगरानी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (CFSO) द्वारा की जा रही है। कुल 56 अधिकारी नियमित स्वच्छता और खाद्य मानकों की निगरानी कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अभियानों का संचालन संकट मोचन मार्ग स्थित कार्यालय से किया जा रहा है। मेले में होटलों, ढाबों और छोटे खाद्य स्टॉलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा टीम को कच्चे माल की गुणवत्ता और खाना पकाने की प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

**ब्रेकिंग न्यूज** 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगी महाकुंभ

## महाकुम्भ मेला में स्थिति मीडिया सेंटर का पत्र सूचना कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों का लिया गया जायज़ा

पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र स्थित मीडिया सेंटर का दौरा किया। इस दौरान प्रधान महानिदेशक ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायज़ा लिया तथा पीआईबी और सीबीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पीआईबी तथा सीबीसी के अधिकारियों को कार्य में समन्वयन स्थापित करने तथा प्रचार-प्रसार से जुड़े कार्यों के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। प्रधान महानिदेशक ने महाकुंभ मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डिजिटल प्रदर्शनी "जनभागीदारी से जन कल्याण" का भी अवलोकन किया तथा अधिकारियों को प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार तथा प्रदर्शनी देखने आने वाले दर्शकों को केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही जनकल्याणकारी कार्यों एवं नीतियों से अवगत कराने को कहा। उक्त प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा महाकुंभ मेले के दौरान 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की जा रही है

जिसमें केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों एवं पहलो से अवगत कराना है। जिससे वह इन नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ ले सके।

## 'जन भागीदारी से जन कल्याण' डिजिटल प्रदर्शनी को बड़ी संख्या में श्रद्धांलुओं ने देखा

महाकुम्भ प्रयागराज में त्रिवेणी मार्ग पर प्रदर्शनी परिसर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकता के महाकुम्भ में 'जन भागीदारी से जन कल्याण' और भारत सरकार की विगत 10 वर्षों में उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों एवं योजनाओं पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी को आज रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने देखा और इसे ज्ञानवर्धक बताया। 13 जनवरी से शुरू प्रदर्शनी में एनामॉर्फिक वाल, एलईडी टीवी स्क्रीन, एलइडी वाल, होलोग्राफिक सिलेंडर के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली डिजिटल प्रदर्शनी में सभी आयु वर्ग के श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। यह प्रदर्शनी विकास के साथ-साथ विरासत को भी प्रदर्शित कर रही है। प्रदर्शनी में उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, अयोध्या धाम और प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, श्री गुरु गोविन्द सिंह जी का 350 वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व के चित्र प्रदर्शित हैं, जो दर्शकों को खूब भा रहे हैं। दर्शक प्रदर्शनी परिसर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की डिजिटल प्रदर्शनी के साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं प्रकाशन विभाग के स्टाल का भी अवलोकन कर रहे हैं। दर्शकों को राष्ट्रीय एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, वेव्स, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्यांजली, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आज़ाद भारत के तीन नये कानून, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ-साथ नारी सशक्तिकरण एवं अन्य योजनाओं की जानकारी दर्शकों और जन सामान्य को मिल रही है।

## मुख्यमंत्री ने अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उन्हें किया नमन

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अमर शहीद गेंदसिंह के 20 जनवरी को शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंदसिंह को याद करते हुए कहा कि सन् 1857 में हुए देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से काफी पहले ही गेंदसिंह जी ने अंग्रेजों की गुलामी और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई थी। बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेतृत्वकर्ता शहीद गेंदसिंह को 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने फांसी दी गई थी। अपने स्वाभिमान तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए गेंदसिंह शहीद हो गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि परलकोट के मुक्ति आंदोलन के नायक गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा।

## एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में भाग लेने वाले कैडेटों द्वारा 'हॉर्स शो'

संवाददाता | नई दिल्ली:

एनसीसी कैडेटों द्वारा 19 जनवरी, 2025 को दिल्ली कैंट स्थित 61 कैवलरी ग्राउंड में वार्षिक 'हॉर्स शो' का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की घुड़सवारी प्रतियोगिता में देश भर से 40 सीनियर डिवीजन और 20 सीनियर विंग कैडेटों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का समापन शानदार 'हॉर्स शो' और पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। कैडेटों ने टेंट पेगिंग और शो जंपिंग के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन किया।घुड़सवारी प्रतियोगिता में अंडर ऑफिसर अंश कर्णावत (राजस्थान निदेशालय) और जूनियर अंडर ऑफिसर वड्लमुडी लोकेश (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना निदेशालय) को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार घोषित किया गया। सार्जेंट भूमिका कंवर (दिल्ली निदेशालय) सर्वश्रेष्ठ महिला घुड़सवार बनीं, जबकि अंडर ऑफिसर स्वर्णिका राठौड़ (राजस्थान निदेशालय) उप-विजेता रहीं। टेंट पेगिंग के लिए डॉ. रूप ज्योति शर्मा ट्रॉफी सीनियर अंडर ऑफिसर हर्षित सिंह (उत्तर प्रदेश निदेशालय) को दी गई और डीजी आरवीएस ट्रॉफी सार्जेंट वतनदीप सिंह (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय) ने जीती। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि घुड़सवारी और इससे जुड़े प्रशिक्षण कैडेटों में अनुशासन, धैर्य और सहनशक्ति जैसे गुणों का विकास करते हैं, जो उनके जीवन के हर क्षेत्र में सहायक होते हैं। कार्यक्रम में आइजोल के मिज़ो हाई स्कूल के कैडेटों द्वारा एक मनमोहक बैंड प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। एनसीसी के पास वर्तमान में 12 निदेशालयों के तहत 20 राइडिंग इकाइयां और 294 घोड़े हैं, जो कैडेटों को घुड़सवारी में उत्कृष्टता हासिल करने के अवसर प्रदान करते हैं। एनसीसी रिमाउंट एंड वेटरनरी इकाइयों में कैडेटों को सालभर कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2024 में एनसीसी कैडेटों ने कई क्षेत्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पांच स्वर्ण, चार रजत और एक कांस्य पदक जीते। तीन कैडेटों ने जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई किया।

## रामन अनुसंधान संस्थान के संकाय को गेट्स-कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया

Koytur times

जगदलपुर: पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 23 मार्च 2025 (दिन रविवार) दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धा बनाना तथा बर्हिमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश कराया जाता है, एवं शाला का पूर्ण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत कक्षा 12 वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।

### वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो

योजना के तहत छात्रों के चयन का मापदण्ड-पात्रता शर्तें-विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य में मान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाण धारक हो।विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामील होने के पात्र होंगे।पिता-पालक की आय समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।

### कक्षा 4थीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे

निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनपरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

## आईआईटी बॉम्बे में क्वांटम सेंसिंग हब की प्रारंभिक बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया गया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के तहत आईआईटी बॉम्बे द्वारा स्थापित क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी हब, क्यूमेट टेक फाउंडेशन ने साझा दृष्टिकोण को परिभाषित करने, मील के पत्थर स्थापित करने और सहयोग आधारित प्रणाली पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र के कुछ सर्वश्रेष्ठ लोगों को एक साथ लाया। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी पर केंद्रित, क्यूमेट, एक सेक्शन 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी, परिणाम आधारित अनुसंधान, निधियों के प्रबंधन और सदस्य संस्थानों के बीच अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नेतृत्व केंद्र के रूप में कार्य करती है। किक-ऑफ मीटिंग ने आगे के लिए रणनीतियों को चिन्हित किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव प्रो. अभय करंदीकर ने किक ऑफ मीटिंग का उद्घाटन करते हुए कहा, ''क्यूमेट टेक फाउंडेशन की स्थापना क्वांटम उत्कृष्टता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देश के कुछ सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एकजुट करके, हमारा लक्ष्य क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी में अभूतपूर्व प्रगति करना है, जो न केवल भारत को लाभान्वित करेगी, बल्कि वैश्विक क्वांटम इकोसिस्टम में भी योगदान देगी। भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि अनुसंधान को ऐसे लाभों तक बढ़ाया जाए, जो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिला सकें।'' इस अवसर पर आईआईटी बॉम्बे के डीन (आर एंड डी) प्रोफेसर सचिन पटवर्धन और डीन (रणनीति) प्रोफेसर केपी कलियप्पन भी उपस्थित थे। क्यूमेट टेक फाउंडेशन की परियोजना निदेशक प्रोफेसर कस्तूरी साहा ने बताया, ''क्यूमेट का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, कार्यबल प्रशिक्षण और नवाचार को आगे बढ़ाकर क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी और इमेजिंग में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करना है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और अनुप्रयोगों को जोड़ना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक खोज में परिवर्तनकारी समाधान लाना है।'' क्यूमेट टेक फाउंडेशन के सीईओ किरण शेष ने बताया, ''क्यूमेट हब की संरचना जटिल है, जिसमें भारत भर में स्थित 16 संस्थान और 40 अनुसंधानकर्ता शामिल हैं। शुरुआती बैठक उद्देश्य की साझा भावना पैदा करने और सहयोग, सहकारिता और प्रभावी संवाद के माध्यम से साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह को प्रेरित करने के लिए डिजाइन की गई है।'' एनक्यूएम के तहत बनाए गए चार विषयगत केंद्रों में से एक क्यूमेट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी में मौलिक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों को जोड़ना है, जो एनक्यूएम के तहत चार फोकस क्षेत्रों में से एक है। वे जिन तकनीकों पर काम करेंगे, उनमें पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर, प्रोफेसर कस्तूरी साहा की प्रयोगशाला में तैयार क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप शामिल हैं। ये और कई अन्य तकनीकें भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी।

## मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 137 करोड़ के कार्यों का आज करेंगे भूमिपूजन और लोकार्पण

रायपुर, छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपराह्न में 3.30 बजे सारंगढ़ के खेलभांठा मैदान में लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से जिले के कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण कर ली है। इसमें विशेष कार्य, संयुक्त जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन, जिला चिकित्सालय भवन का भूमिपूजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ में बीपीएचयू भवन निर्माण और जिला चिकित्सालय के लिए आईपीएचएल भवन निर्माण का भूमिपूजन, जिले में लगभग 8 करोड़ की लागत से गोदाम निर्माण कार्य का भूमिपूजन विशेष रूप से शामिल है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण से जिले के सभी विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे, जिससे सभी नागरिकों को एक ही स्थान में सभी कार्य हो जाएंगे। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय के निर्माण से जिला स्तर का हॉस्पीटल सेटअप स्थापित होगा। सभी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होने से जिले के नागरिकों को अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार गोदाम निर्माण से धान खरीदी के दौरान संग्रहण कार्य में सुविधा मिलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जिला कार्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे।

## ब्रेकिंग न्यूज 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित

# कानूनी भूमि स्वामित्व के साथ ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान कर ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देना है। यह योजना ड्रोन और जीआईएस जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर संपत्ति सीमांकन करती है, जिससे संपत्ति मुद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, बैंक ऋण तक पहुंच आसान होती है, संपत्ति विवाद कम होते हैं और ग्राम-स्तरीय व्यापक योजनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। सच्चे ग्राम स्वराज की प्राप्ति की दिशा में यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त करने में सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2025 को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड ई-वितरित किए। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया और स्वामित्व योजना के माध्यम से कानूनी भूमि स्वामित्व के साथ ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण लंबे समय से अधूरा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण संपत्ति मालिकों के पास कानूनी रिकॉर्ड नहीं थे। इस वजह से उन्हें अपनी संपत्ति को वित्तीय संसाधन के रूप में उपयोग करने और बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। इन चुनौतियों के समाधान के लिए स्वामित्व योजना लाई गई। यह योजना ड्रोन तकनीक और उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण का उपयोग कर ग्रामीण भूमि सीमांकन की प्रक्रिया को सरल और सटीक बनाती है। योजना के तहत अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3.46 लाख गांवों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 92% गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, और लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने 100% ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। हरियाणा और उत्तराखंड ने ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयार करने दोनों में 100% सफलता प्राप्त की है। स्वामित्व योजना के सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की श्रीमती सुनीता को 25 साल के लंबे विवाद के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन का स्वामित्व मिला, जिससे उनके परिवार को स्थिरता और शांति प्राप्त हुई।

### स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई

जम्मू और कश्मीर की श्रीमती स्वर्ण कांतरा को पहली बार उनकी भूमि का कानूनी स्वामित्व प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिली। राजस्थान के श्री सुखलाल पारगी ने अपने संपत्ति कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपये का बैंक ऋण प्राप्त किया। स्वामित्व योजना न केवल ग्रामीण विवादों को सुलझाने में मदद कर रही है, बल्कि पंचायत स्तर पर राजस्व बढ़ाने और बेहतर योजना बनाने में भी सहायक है। मध्य प्रदेश के बिलकिसगंज गांव में स्वामित्व मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम पंचायत ने विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया है। इस पहल ने ग्राम पंचायतों को सटीक भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराए हैं, जिससे बेहतर सेवा वितरण और पारदर्शी शासन सुनिश्चित हो रहा है । योजना के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए अब तक 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, जिसका मूल्य 132 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। डिजिलॉकर के माध्यम से लाभार्थियों को डिजिटल संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

### जल संरक्षण के विभिन्न उपाय

मंत्रालय अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वामित्व योजना की सफलता को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है। मार्च 2025 में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के 40 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ भूमि प्रशासन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मई 2025 में वाशिंगटन में विश्व बैंक के भूमि प्रशासन सम्मेलन में भारत के मॉडल को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। स्वामित्व योजना केवल एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बन चुकी है। यह भूमि स्वामित्व से जुड़ी पुरानी समस्याओं को विकास और सशक्तिकरण के अवसरों में बदल रही है। उच्च-तकनीकी ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल संपत्ति कार्ड के माध्यम से यह योजना ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक नई क्रांति ला रही है।

## डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "सीएसआईआर मुंबई हब स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और डीप-टेक उन्नयन को बढ़ावा देगा"

**स्टार्ट-अप, एमएसएमई और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधा:**

एमसीबी छत्तीसगढ़

नई दिल्ली: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 17 जनवरी को वर्चुअल मोड के माध्यम से मुंबई में भारत के अपनी तरह के पहले सीएसआईआर मेगा ''इनोवेशन कॉम्प्लेक्स'' का उद्घाटन किया और इसे स्टार्टअप्स और उद्योगजगत के हितधारकों को समर्पित किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया मुंबई का नया इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, नौ मंजिलों में फैला एक विशाल अत्याधुनिक परिसर है, जिसमें 24 ''रेडी टू मूव'' वाली इनक्यूबेशन प्रयोगशालाएं हैं, साथ ही नवोन्मेषी स्टार्टअप, एमएसएमई, उद्योग और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के लिए सुसज्जित कार्यालय और नेटवर्किंग स्थान भी हैं। यह मेगा सुविधा सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्योग सहित हितधारकों को नियामक प्रस्तुतियां और अनुपालन के लिए आवश्यक एसओपी-संचालित अध्ययनों के लिए उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषज्ञता और नियामक सहायता प्रदान करेगी। इस परिसर में नवीन स्टार्ट-अप्स, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, एमएसएमई, भारत और विदेश की डीप-टेक कंपनियों, सार्वजनिक-वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी करने वाली कंपनियों के लिए तैयार विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन प्रयोगशालाएं और आईपी/व्यवसाय विकास सहायता शामिल है। दर्शकों के उत्साह को देखते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ''यह उद्घाटन तो बस शुरुआत है। हम भविष्य की संभावनाओं और भारत की विकास गाथा में इस इनोवेशन कॉम्प्लेक्स के योगदान को लेकर उत्साहित हैं।''

# स्वास्थ्य से समृद्धि के मंत्र से ही आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा - मुख्यमंत्री श्री साय

Koytur times

रायपुर, छत्तीसगढ़: हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा स्वास्थ्य से समृद्धि के मंत्र से ही आगे बढ़ रही है। आज छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रहा है। एक समय था जब कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोग दिल्ली-मुंबई जाते थे। आज गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार रायपुर शहर के सेवाभावी डॉक्टर कर रहे हैं। हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों का अत्याधुनिक तकनीक से उपचार रायपुर के अस्पतालों में हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहतर संसाधन, आवश्यक अधोसंरचना विकसित उपलब्ध कराने के साथ - साथ डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ की भर्ती की जा रही है ।

हमारी सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू की है।आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के नागरिकों को पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज तथा एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जटिल रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय और 4 निजी मेडिकल कालेजों सहित कुल 14 मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में चार नये मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम में मेडिकल कॉलेज बनने से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि आईएमए जैसे संगठन चिकित्सकों की आवाज़ बनने के साथ डॉक्टर और मरीज के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं । स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। चिकित्सकगणों के सहयोग और समर्पण से ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नए मुकाम पर ले जाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। उन्होंने चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सिकलसेल की स्क्रीनिंग में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। यहां एक करोड़ 29 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। राज्य में सिकल सेल अनुसंधान संस्थान की स्थापना और बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए 48 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने आईएमए रायपुर को विश्वास दिलाया कि सरकार चिकित्सकों और जनहित के कामों में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने भी संबोधित किया। आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सोलंकी ने राज्य में चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए एसोसिएशन की ओर से हरसंभव सहयोग दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आईएमए शासन और चिकित्सा सेवा प्रदाता के बीच समन्वय का दायित्व पूरी प्रतिबद्धता से निभाएगी। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, आईएमए छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. प्रभात पाण्डेय, डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना सहित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित थे।

## जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जल्द शुरू होगा: स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल

संवाददाता | जगदलपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण हो रहा है। यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज के सामने बन रहा है, जिससे अंचल के लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जगदलपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और सिटी स्कैन, एमआरआई जैसी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड का विस्तार, सीसीटीवी परिचालन हेतु ऑपरेटर नियुक्ति और अस्पताल की सफाई, ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल की सुविधाओं और निःशुल्क दवा योजना की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

## जिले के 27 लोगों को प्रदान किया गया भूमि अधिकार अभिलेख जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिधि एवं हितग्राहीगण हुए शामिल

गरियाबंद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख भूमि पट्टों का वितरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 27 लोगों को भूमि अधिकार अभिलेख सौंपे गए। गरियाबंद के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, और हितग्राहियों ने भाग लिया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे और आधुनिक तकनीक से गांवों की मैपिंग कर भू-अधिकार दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इससे लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिला है, जो शासकीय योजनाओं के लाभ और बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना से आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। योजना ने भूमि विवाद सुलझाने, भ्रष्टाचार रोकने, और आपदा के समय मुआवजा दिलाने में मदद की है। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर इसे पहचान दी गई है, जिससे भू-स्वामित्व की स्पष्टता बढ़ी है।

# 15 फरवरी तक किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि एकमुश्त देंगे - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर, छत्तीसगढ़, सरकार ने 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर की राशि किसानों को एकमुश्त देगी। इसका निर्णय आज केबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस अवसर पर किसानों के सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रूपए के भूमिपूजन कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने 38 करोड़ रूपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आबंटन, डेढ़ करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक व सामग्री प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिंचित भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा 144 सालों बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में साढ़े चार एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है। यहां छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही हैं। 3100 रूपये में धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है। आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले एक साल में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद श्री राधेश्याम राठिया एवं श्रीमती कमलेश जांगड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, विधायक बिलाईगढ़ श्रीमती कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक श्री शमशेर सिंह, श्रीमती केराबाई मनहर, सुश्री कामदा जोल्हे, श्री ज्योति पटेल, श्री जगन्नाथ पाणिग्राही सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

## मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ सुनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात'

रायपुर, छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रेडियो वार्ता "मन की बात" सुनी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यह कार्यक्रम वास्तव में देशवासियों की उपलब्धियों, मानवता की सेवा के कार्यों और नवाचार की जानकारियों का अनूठा संगम है । जहां प्रधानमंत्री जी की ज्ञान, विज्ञान की बातें, स्वस्फूर्त रूप से देशवासियों के देश के लिए समर्पित होकर किए जा रहे कार्यों और नई नई जानकारियां सुनने वालों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। 'मन की बात' में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के गुरुघासीदास तमोरपिंगला टाइगर रिजर्व की चर्चा करते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीते दो महीनों में हमारे देश में दो नए टाइगर रिजर्व जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है -मध्यप्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों, युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट अप, महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयासों का उल्लेख किया। देश की महान विभूतियों स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाषचंद बोस से युवाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देशवासियों से कहा कि हम सभी अपने अपने काम से अपने देश को हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगाँठ पर संविधान सभा की सभी महान विभूतियों को नमन किया। उन्होंने मन की बात में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में परस्पर सहयोग, डॉ० राजेंद्र प्रसाद जी के मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अवसर की समानता पर प्रेरणादायक संबोधन के अंश उनकी आवाज में सुनवाए।

## अवैध शराब पर आबकारी विभाग बीजापुर की कार्यवाही

संवाददाता | बीजापुर

बीजापुर: कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर और उपायुक्त आबकारी श्री आशीष कोसम के मार्गदर्शन में 17 जनवरी 2025 को जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व मे आबकारी टीम बीजापुर ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी वृत्त भोपालपट्टनम ग्राम बासागुड़ा थाना बासागुड़ा से 500 मीटर की दुरी पर साप्ताहिक बाजार के मध्य तिरुपति जंघम नाम के व्यक्ति द्वारा किराना दुकान के माध्यम से अवैध मदिरा का विक्रय किया जा रहा था। मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम मौके पर घटना स्थल पर पहुंची परन्तु आरोपी अवैध शराब को अपने घर के एक कमरे मे छुपा कर फरार हो चूका था। स्थानीय पुलिस की मदद से तथा गांव के सरपंच एवं अन्य गवाहों के उपस्थिति मे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया जहाँ से बड़ी मात्रा मे नॉन ड्यूटी पेड एवं ड्यूटी पेड अवैध शराब जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2), 36, 59 (क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया है। कार्यवाही के दौरान नॉन ड्यूटी पेड (मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना विक्रय हेतु कुल 66.17 बल्क लीटर 273 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की, 84 नग मैकडॉवेल्स नंबर 1 व्हिस्की, 7 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की प्रति नग 180 उस 1 नग किंग फिशर बियर 650 उस ड्यूटी पेड कुल 31.50 बल्क लीटर 3 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्क, 11 नग ब ब्लैक, 16 नग फ्रंटलाइन व्हिस्की, 8 नग वाइट एंड ब्लू व्हिस्की, 4 नग आफ्टर डार्क व्हिस्की प्रति नग 750 लीटर प्राप्त किया गया। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्रीराम कावरे, आरक्षक शिवनारायण सेठिया, भरत वट्टी, नगर सैनिक मनोज एक्का तथा थाना बासागुड़ा के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

# इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल' विषय पर तीन दिव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा

रायपुर, छत्तीसगढ़ : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर कल 20 जनवरी से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास सहयोग लिमिटेड, बारामूला (जम्मू-कश्मीर) के संयुक्त वैज्ञानिकों के लिए ''कृषि, विज्ञान एवं शिक्षा के लिए'' ग्लोबल रिसर्च फर्स्ट'' विषय पर तीन दिव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 20 से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेता करेंगे। कार्यक्रम की अधीरा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख डॉ. वृषभ चंदेल जायेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक धारसींवा श्री अनुज शर्मा और उपाध्यक्ष रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ''कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल'' में देश भर के 21 राज्यों में तीन दिव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 400 से अधिक कृषि वैज्ञानिक और शोधार्थी शामिल होंगे। सम्मेलन में वैश्विक परिक्षेत्र में भूमि, जल और पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मेलन के अवसर और सम्मेलन में विचार-मंथन और मंच का बेहतर उपयोग कर लगातार होने वाली कमियों को लक्ष्यों के रास्ते तलाशे जाएंगे। आने वाले समय में खाद्यान, दल्हन, तिलहन और अन्य आवश्यक कृषि उद्यमों जैसे खाद्यान, दलहन, तिलहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पैदावार को पूरा करने के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा और इस सदन में नई रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में संबंधित विषयों पर संग्रह और शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र और पोस्ट प्रस्तुत किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जो विश्वविद्यालय अपने 28 कृषि संकाय, 4 कृषि वैज्ञानिक महाविद्यालय, 1 खाद्य शैक्षणिक महाविद्यालय, 08 अनुसंधान केन्द्र एवं 27 कृषि विज्ञान के माध्यम से संचालित कर रहा है। ।। विश्वविद्यालय के विभिन्न विश्वविद्यालयों में वर्तमान में लगभग 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, स्नातक स्तर के विद्यार्थी 2763 में अध्ययनरत हैं, स्नातक स्तर के विद्यार्थी 500 में तथा स्नातक विद्यार्थी (पी.एच.डी.) में 115 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के दृश्य 52 बीजाणु की लगभग 162 जनजातियों का विकास किया गया है और कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, किसानों के कल्याण, युवाओं के कौशल विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए कई अहम निर्णय लिए गए

रायपुर, छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, किसानों के कल्याण, युवाओं के कौशल विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों में राज्य के 27 लाख किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अतिरिक्त 800 रुपए प्रति क्विंटल की राशि फरवरी 2025 में एकमुश्त आदान सहायता के रूप में किसानों को प्रदान करेगी। यह कदम किसानों की आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान उपार्जित अतिरिक्त धान को नीलाम करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बाजार की मांग और कीमतों में स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रिपरिषद ने एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं, विशेषकर मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को राहत देने का निर्णय लिया। इन उद्योगों को ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रति यूनिट एक रुपए की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट उन उद्योगों के लिए होगी जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हैं या जो एक मेगावाट से कम हैं और जिनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है। यह कदम औद्योगिक मंदी के दौरान प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य के कलाकारों और लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन करते हुए आर्थिक सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब कलाकारों और लेखकों को अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे आर्थिक कठिनाइयों के समय बेहतर मदद प्राप्त कर सकेंगे। युवाओं को वित्तीय क्षेत्र में कौशल प्रदान करने और उनके ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। यह छात्र स्किलिंग प्रोग्राम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए संचालित किया जाएगा, जिससे वे वित्तीय बाजार, निवेश और वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकें। राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग के तहत एक नए पद का सृजन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने अपर आयुक्त आबकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-15) के पद को स्वीकृति दी है। यह कदम विभाग के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, नवा रायपुर अटल नगर में श्री सत्य सांई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को पांच एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर में 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित पांच वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एकमुश्त निपटान के लिए लागत मूल्य से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय किया जाएगा। इससे अटकी हुई संपत्तियों का तेजी से निपटान होगा और प्राधिकरण को वित्तीय मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत राज्य में एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत, मकान निर्माण पूरा होने या गृह प्रवेश के समय हितग्राहियों को अनिवार्य राज्यांश के रूप में 1450 करोड़ रुपए और अतिरिक्त राज्यांश के रूप में 538 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिपरिषद ने रेडी-टू-ईट निर्माण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में यह कार्य पांच जिलों में लागू किया जाएगा। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मदद मिलेगी। पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए जारी अध्यादेश की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने और वंचित वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

## कलेक्टर दर पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की मजदूरी दर स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रशासनिक मद से कलेक्टर दर पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की मजदूरी कलेक्टर दर के आधार पर अक्टूबर एवं नवम्बर का एरियर्स तथा माह दिसम्बर का वेतन की राशि 51 हजार 824 रूपए स्वीकृत की गई है। उक्त राशि जिला पंचायत कांकेर, जनपद पंचायत अंतागढ़, चारामा और कोयलीबेड़ा हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रशासनिक मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगी।

# नवीन जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष से पहले मिली पहली महिला जिला पंचायत सीईओ

एमसीबी, छत्तीसगढ़: नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को महिला जिला पंचायत अध्यक्ष से पहले पहली महिला जिला पंचायत सीईओ मिल गई है। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को राज्य प्रशासनिक सेवा अफसरों की जारी की गई तबादला सूची में कोरिया जिले की अपर कलेक्टर अंकिता सोम को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। अंकिता सोम नई जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की पहली जिला पंचायत सीईओ होंगी। कोरिया से कटकर अलग जिला पंचायत बने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला पंचायत में पहली बार जिला पंचायत के चुनाव होंगे। शनिवार को अंकिता सोम ने कार्यालय पहुंचकर पदभार भी ग्रहण कर लिया है। अंकिता सोम ने कहा बेहतर तरीके से नए जिला पंचायत का निर्वाचन करवाना उनकी पहली प्राथमिकता होंगी। वही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जिला पंचायत क्षेत्र के हर पंचायत में पहुंचाने के लिए वे कार्य करेंगी। अंकिता सोम ने आशा जताई कि सभी के सहयोग एवं समन्वय से शासन के जनहितैषी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास उनके द्वारा किया जायेगा। गौरतलब है कि अंकिता सोम 2014 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर है। इससे पहले वे कोरिया जिले में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थी। इसके अलावा वे दुर्ग और गरियाबंद जिले में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी है। नए जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला पंचायत का अध्यक्ष पद एसटी महिला के लिए पहले ही आरक्षित हुआ है। अब पहली जिला पंचायत सीईओ के पद पर अंकिता सोम द्वारा पदभार संभालने के बाद नए जिला पंचायत की कमान नारी शक्ति के हाथों में होगी ।

# शहीद गेंद सिंह ने ब्रिटिश और मराठा शासकों के खिलाफ किया था 1824 में परलकोट विद्रोह की शुरूवात

## शहीद गेंद सिंह शहादत दिवस पर विशेष लेख/ महेन्द्र सिंह मरपच्ची

शहीद गेंद सिंह का नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा की तरह आज भी याद रखा गया है। वेंत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश और मराठा शासकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनके बलिदान ने पूरे छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया और उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन और उनका संघर्ष एक प्रेरणा है जो हमें अपने अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की ताकत देता है। शहीद गेंद सिंह का जन्म 1795 के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के परलकोट गांव में हुआ था। वे बस्तर रियासत के एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम राम सिंह था जो परलकोट के जमींदार थे और उनकी माता का नाम देवी कंवर था। राम सिंह और देवी कंवर दोनों ही अपनी अच्छाई और प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता ने परलकोट के प्रशासन में सक्रिय भाग लिया और उनके माता-पिता ने अपने बेटे को न केवल परंपराओं और संस्कृति से परिचित कराया बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय और लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। गेंद सिंह का बचपन एक संपन्न परिवार में बीता और उन्हें प्रशासन की जटिलताओं और जनता के साथ संवाद की कला से परिचय हुआ। हालांकि वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त नही कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के समाज और आदिवासी संस्कृति से गहरी समझ विकसित की। अपने व्यक्तित्व में साहस, नेतृत्व, और संघर्ष के गुण विकसित करने के कारण वे बहुत जल्द अपने क्षेत्र के सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गए।

गेंद सिंह की शिक्षा पारंपरिक रूप से उनके परिवार और उनके समाज से ही प्राप्त हुई। उन्हें प्रशासन, युद्धकला और लोगों की समस्याओं के समाधान में उत्कृष्टता हासिल की थी। उनके पिता राम सिंह के नेतृत्व में उन्होंने परलकोट क्षेत्र में प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन सीखा और साथ ही साथ घुड़सवारी, धनुष-बाण और युद्धकला में महारत प्राप्त की। उनके लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था समाज की सेवा करना और जनता की भलाई के लिए काम करना। शहीद गेंद सिंह आदिवासी संस्कृति के गहरे जानकार थे और अपने क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से भली-भांति अवगत थे। यही कारण था कि उन्हें उनके समाज में एक आदर्श नेता के रूप में सम्मानित किया गया।

### शहीद गेंद सिंह की क्रांति और परलकोट विद्रोह छत्तीसगढ़ का पहला संघर्ष रहा

शहीद गेंद सिंह की क्रांति ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समाज को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। परलकोट विद्रोह, जो 1824 से 1825 के बीच हुआ, छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी क्रांति मानी जाती है। इस विद्रोह का नेतृत्व शहीद गेंद सिंह ने किया था और यह ब्रिटिश सरकार के शोषण, उनके नए करों और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ था। 1824 के आसपास ब्रिटिश शासन ने छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत किया था। आदिवासी समाज पहले से ही विभिन्न शोषणों और अत्याचारों का सामना कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के कारण उनकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय आदिवासियों से न केवल उनकी ज़मीन और संसाधन छीन लिए थे, बल्कि नए करों और अत्यधिक कर वसूलने की नीतियों ने उनकी स्थिति को दयनीय बना दिया था। इसके अलावा मराठों के शोषण और उनकी अधीनता के कारण आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ रहा था। यह असंतोष तब और बढ़ गया जब अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए वहां के पारंपरिक नियमों और अधिकारों को नकार दिया।

### गेंद सिंह का नेतृत्व और परलकोट विद्रोह की शुरुआत

गेंद सिंह जो उस समय परलकोट के जमींदार थे, उन्होने इन समस्याओं को गहरे से महसूस किया और उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए एक क्रांति का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में परलकोट विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे ब्रिटिश और मराठा शासन के खिलाफ आदिवासी समाज का एक सशक्त प्रतिकार माना जाता है। गेंद सिंह ने आदिवासी समाज को एकजुट किया और उनके साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश शासकों और मराठों के खिलाफ हथियार उठाए। उनका संघर्ष केवल ज़मीन और संसाधनों की रक्षा का नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था, जो आदिवासियों के अधिकारों की पुनः स्थापना की ओर अग्रसर था।

### विद्रोह की रणनीति और युद्धकला से निपुण था गेंद सिंह

गेंद सिंह ने अपनी रणनीति में पारंपरिक युद्धकला और प्रकृति से प्राप्त साधनों का उपयोग किया। उन्होंने स्थानीय आदिवासियों के परंपरागत हथियारों जैसे धनुष-बाण, तीर, तलवार, और भाले का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने मधुमक्खियों का भी इस्तेमाल किया, जो ब्रिटिश सैनिकों के लिए अप्रत्याशित था। गेंद सिंह की यह रणनीति अंग्रेजों को परेशान करने में सफल रही और उन्होंने कई बार ब्रिटिश सेना को घेर लिया और नुकसान पहुँचाया। गेंद सिंह की सेना के अधिकांश सदस्य आदिवासी थे, जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे। उन्होंने भुजरिया और अबूझमाड़िया आदिवासियों को साथ लिया और एक सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष में वे घोड़े का उपयोग करते हुए युद्ध करते थे, जो एक अनूठी रणनीति थी। उनका नेतृत्व और साहस इतना प्रभावी था कि उन्होंने ब्रिटिश और मराठा शासकों के लिए खतरों की घंटी बजा दी थी।

### गेंद सिंह के खिलाफ ब्रिटिश प्रशासन का प्रतिकार

ब्रिटिश शासक गेंद सिंह और उनके विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए तेजी से कदम उठाने लगे। 1824 के अंत तक, अंग्रेजों ने बस्तर और परलकोट के क्षेत्रों में सैनिक भेजने शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश सेना ने स्थानीय आदिवासियों को दबाने के लिए सख्त दमन नीतियों का सहारा लिया। हालाँकि गेंद सिंह का संघर्ष जारी रहा, ब्रिटिश प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 12 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को अंग्रेजों ने कूटनीति के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया और 20 जनवरी 1825 को उन्हें परलकोट के महल के सामने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। यह घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने पूरे क्षेत्र में क्रांति की एक नई धारा को जन्म दिया। आज उनकी शहादत को 200 वर्ष हो चुके हैं। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक संघर्षों में से एक है, जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। परलकोट महल जहां उन्हें फांसी दी गई, आज भी उनके बलिदान और संघर्ष की गवाही देता है। यह स्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण साक्षी है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें। इतिहास में 200 वर्षों का यह अंतराल हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष बलिदान की मांग करता है। शहीद गेंद सिंह का जीवन और उनका बलिदान आज भी छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। राज्य और समाज का कर्तव्य है कि वे उनकी स्मृति को जीवित रखें और उनके नाम पर विशेष स्मारक और संग्रहालय स्थापित करें। उनका योगदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की प्रेरणा देता है।

### परलकोट विद्रोह और गेंद सिंह की बलिदान ने आदिवासियों को किया एकजुट

गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ परलकोट विद्रोह केवल एक स्थानीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के लिए एक चेतावनी था। उनकी शहादत ने आदिवासियों को यह संदेश दिया कि उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना जरूरी है। इस विद्रोह ने छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलाया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए आदिवासियों को एकजुट किया। गेंद सिंह के बलिदान के बाद छत्तीसगढ़ में और बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया। उनका नाम हमेशा छत्तीसगढ़ के पहले शहीद के रूप में याद किया जाएगा, और उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। शहीद गेंद सिंह की क्रांति और परलकोट विद्रोह छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है। उनका संघर्ष आदिवासी समाज की अधिकारों की रक्षा के लिए था और उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य में बलिदान किया। उनकी शहादत ने न केवल बस्तर क्षेत्र बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को बढ़ावा दिया। उनकी क्रांति आज भी हमें यह सिखाती है कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी होता है।

### शहीद गेंद सिंह की वंशजों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की हैं?

छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद गेंद सिंह के वंशजों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। परलकोट में रहने वाले वंशज नीरशंकी और उनका परिवार खेती-किसानी पर निर्भर है, लेकिन पर्याप्त जमीन न होने और आर्थिक तंगी के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में शामिल हुए नीरशंकी ने कहा कि सरकार उनके परिवार की मदद करें और उन्हें पेंशन प्रदान की जाए। गेंद सिंह के वंशजों ने बताया कि उनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। किसी तरह से परिवार का गुजारा हो रहा है। गेंद सिंह के वंशज कांकेर, जगदलपुर और आसपास के जिलों में रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। गेंद सिंह के नाम पर पुरस्कार की मांग की है कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान में शहीद गेंद सिंह के नाम पर पुरस्कार दिया जाए। इससे न केवल उनके बलिदान का सम्मान होगा बल्कि उनके वंशजों को भी सरकार से प्रोत्साहन मिलेगा।

शहीद गेंद सिंह को शत-शत नमन।